



दक्षिण भारत राष्ट्रमत

தக்ஷிண் பாரதத் ராஷ்ட்ரமத் | தினகரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बंगलूरु से एक साथ प्रकाशित



5 घबराइए मत, हर समस्या का होगा समाधान : योगी आदित्यनाथ

6 नफरत बनाम संविधान : लोकतंत्र की असली कसौटी

7 लगातार नौवां बजट पेश कर इतिहास रचेंगी निर्मला सीतारामण

फर्स्ट टेक

भारत-ईयू एफटीए के 2026 में लागू होने की संभावना : गोगयल

नई दिल्ली/भाषा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोगयल ने मंगलवार को कहा कि महत्वाकांक्षी भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) वर्ष 2026 में लागू हो सकता है। उन्होंने इस ऐतिहासिक व्यापार समझौते की वार्ता संपन्न होने की घोषणा के कुछ घंटों बाद यह बात कही। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग की प्रमुख की भारत की राजकीय यात्रा पर आयोजित एक विशेष संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल का जवाब देते हुए गोगयल ने कहा, “हर समझौता अपने आप में खास होता है और यह एक शानदार समझौता है। इसकी कानूनी बारीकियों की जांच बहुत तेजी से की जाएगी...। हमें उम्मीद है कि हम वर्ष 2026 के भीतर ही इस समझौते के लागू होने का जश्न मनाएंगे।”

अरिजीत सिंह ने पार्व गायन को कहा ‘अलविदा’

नई दिल्ली/भाषा। बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय और सफल गायकों में से एक अरिजीत सिंह अब पार्श्वगायन न करने की मंगलवार को घोषणा की और अब तक के अपने इस सफर को शानदार बनाया। अरिजीत ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, “मैं इस सफर को यहीं समाप्त कर रहा हूँ, यह एक शानदार सफर रहा।” उन्होंने लिखा कि वह अब पार्श्वगायक के रूप में कोई नया काम नहीं करेंगे। उनके इस फैसले से उनके प्रशंसकों में सदमे की लहर दौड़ गयी। अरिजीत हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय और महंगे गायकों में से एक हैं। उन्होंने पोस्ट में लिखा, नमस्ते, आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। इतने वर्षों तक मोताओं के रूप में मुझे इतना प्यार देने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मैं अब पार्श्वगायक के रूप में विदा ले रहा हूँ। मैं इसे अलविदा कह रहा हूँ। यह एक शानदार सफर रहा।

मुवनेश्वर में देसी बम विस्फोट में चार लोग घायल

भुवनेश्वर/भाषा। पश्चिम बंगाल के सुंदरपाड़ा इलाके में मंगलवार को हुए एक देसी बम विस्फोट में चार लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, यह घटना यहां एयरफील्ड थाना अंतर्गत आजाद नगर में उस समय हुई जब कुछ लोग किराए के मकान की छत पर अवैध रूप से देसी बम बना रहे थे। भुवनेश्वर के पुलिस उपायुक्त जगमोहन मीणा ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद कहा, “आपराधिक पृष्ठभूमि वाले एस मलिक समेत चार लोग बम विस्फोट में घायल हो गए। घटना के समय वे अवैध रूप से बम बना रहे थे।” इस घटना में मलिक, उसकी मां, दोस्त अमिया रंजन मलिक और एक महिला मित्र घायल हो गई।

28-01-2026 सुबोत 6:07 बजे 29-01-2026 सुबोत 6:35 बजे

BSE 81,857.48 (+319.77) NSE 25,175.40 (+126.75)

सोना 16,680 रु. (24 कैरेट) प्रति ग्राम चांदी 358.910 रु. प्रति किलो

निशान मंडेला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com



केलाश मण्डेला, मो. 9828233434

राजनीति में प्रमुख

राजनीति का प्रमुख धर्म है, केवल सत्ता को पाना। राजनीति का प्रमुख कर्म है, इकट्ठे को लड़वाना। राजनीति का प्रमुख मर्म है, निज दल को ही पुजवाना। राजनीति की प्रमुख शर्मा है। जन चुनाव हार जाना।

भारत-यूरोपीय संघ ने किया ‘सबसे बड़ा समझौता’

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com



दोनों पक्षों ने सुरक्षा व रक्षा सहयोग और यूरोप में भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही से जुड़े दो महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

नई दिल्ली/भाषा। भारत और यूरोपीय संघ ने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर मंगलवार को हस्ताक्षर किए जिसे ‘अबतक का सबसे बड़ा समझौता’ बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और यूरोपीय संघ के शीर्ष नेतृत्व ने व्यापार एवं रक्षा क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने और नियम-आधारित विश्व व्यवस्था की दिशा में काम करने के लिए एक व्यापक एजेंडा पेश किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय संघ के नेताओं उर्सुला वॉन डेर लेयेन और एंटीोनियो कोस्टा की मेजबानी की। इसके बाद दोनों पक्षों ने सुरक्षा व रक्षा सहयोग और यूरोप में भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही से जुड़े दो महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप, भारत और 27 देशों के समूह ने अगले पांच वर्षों के लिए एक संयुक्त व्यापक रणनीतिक एजेंडा पेश किया। मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए वार्ता के समापन सहित कुल 13 समझौतों को अंतिम रूप दिया। व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू होने के बाद से 18 साल लग गए। समझौते पर

व्यापार समझौते की सराहना करते हुए यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष वॉन डेर लेयेन ने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ की साझेदारी यह शक्ति संदेश देगी कि वैश्विक चुनौतियों का सबसे अच्छा समाधान सहयोग है। ये टिप्पणियां यूरोप और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच आईं।

औपचारिक हस्ताक्षर होने में कम से कम छह महीने लग सकते हैं क्योंकि दोनों पक्षों द्वारा इसकी कानूनी जांच-पड़ताल आवश्यक होगी। यूरोपीय संघ और भारत ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत पहली बार 2007 में शुरू की थी, लेकिन कुछ मुद्दों के कारण 2013 में बातचीत

साझेदारी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में स्थिरता को मजबूत करेगी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक व्यवस्था ‘भारी उथल-पुथल’ का सामना कर रही है और ऐसे में भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में स्थिरता को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा, “आज भारत ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता संपन्न किया है।” मोदी ने बयान में कहा, “इससे हमारे किसानों तथा लघु उद्योगों को यूरोपीय बाजार तक पहुंच सुगम होगी और विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में नए अवसर उत्पन्न होंगे।” उन्होंने कहा, “यह मुक्त व्यापार समझौता भारत और यूरोपीय संघ के बीच निवेश को बढ़ावा देगा, नए नवाचार साझेदारियों का निर्माण करेगा और वैश्विक स्तर पर आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करेगा। इसका मतलब यह है कि यह सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं है। यह साझा समृद्धि के लिए एक नया खाका है।”



भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी से दो अरब लोगों का बाजार बना रहे हैं

हैं। उन्होंने कहा, “हमने कर दिखाया। हमने अब तक का सबसे बड़ा समझौता कर दिखाया। हम दो अरब लोगों का बाजार बना रहे हैं।” लेयेन ने कहा, “यह दो दिग्गजों की कहानी है...। दुनिया की दूसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की

वास्तव में पारस्परिक लाभ के दृष्टिकोण से साझेदारी को चुना। एक शक्ति संदेश कि वैश्विक चुनौतियों का सबसे अच्छा समाधान सहयोग ही है।” उन्होंने कहा कि व्यापार समझौते से यूरोपीय निर्यातकों के लिए वार्षिक शुल्क में चार अरब यूरो तक की कटौती होगी और भारत और यूरोप दोनों में लाखों श्रमिकों के लिए रोजगार सृजित होंगे।

था। इसमें निर्यात करीब 76 अरब अमेरिकी डॉलर और आयात 60 अरब अमेरिकी डॉलर का था। वॉन डेर लेयेन ने कहा, “यह (मुक्त व्यापार समझौता) भारत के कौशल, सेवाओं एवं विशाल क्षमता को यूरोप की प्रौद्योगिकी, पूंजी तथा नवाचार के साथ जोड़ता है।” उन्होंने अमेरिकी प्रशासन की व्यापार

देश को फिर से राजा-महाराजाओं के जमाने में धकेला जा रहा है

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) के मुद्दे पर मंगलवार को नरेन्द्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि देश को फिर से राजा-महाराजाओं के



उस जमाने में धकेला जा रहा है, जहां सारी ताकत और संपत्ति गिनती के लोगों के पास होती थी। उन्होंने मनरेगा मजदूरों के साथ हालिया बातचीत का वीडियो ‘एक्स’ पर साझा किया और दावा किया कि मोदी सरकार मजदूरों को गुलाम बनाने वाली सरकार है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, “मोदी जी का मनरेगा को बर्बाद करने का मकसद क्या है? मजदूरों से दिहाड़ी के मोल-भाव का हक छीन लेना, पंचायतों की शक्ति छीन कर उनके हाथ बांधना, राज्यों से अधिकार छीन कर दिल्ली में केंद्रित करना, देश को फिर से राजा-महाराजाओं के जमाने में धकेलना, जहां सारी ताकत और संपत्ति गिनती के लोगों के पास

हो।” राहुल गांधी के अनुसार, देश के करोड़ों श्रमिक एक आवाज में कह रहे हैं कि मनरेगा ने हमारी हालिया बातचीत का वीडियो ‘एक्स’ पर साझा किया और दावा किया कि मोदी सरकार मजदूरों को गुलाम बनाने वाली सरकार है।

लक्षित हमलों की साजिश की विफल

गुजरात एटीएस ने संदिग्ध आतंकी को किया गिरफ्तार

अहमदाबाद/भाषा। गुजरात के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों की हत्या की आतंकी साजिश को विफल करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन— जैश ए मोहम्मद की कट्टरपंथी विचारधारा से कथित रूप से प्रेरित होकर ‘अकेले’ काम करता था। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, आरोपी फैजान शेख पेंगबर मोहम्मद के ‘अपमान’ का बदला लेने के लिए उत्तर प्रदेश भर में लक्षित हत्याओं की साजिश के अंतिम चरण में था। एटीएस ने उसके पास से एक मिरतली और छह कारतूस बरामद किए, जिनका इस्तेमाल वह कथित तौर पर ‘हाई प्रोफाइल’ हत्याओं के लिए करना चाहता था। उन्होंने बताया कि पेश से दर्जी फैजान शेख (22) गुजरात के नवसारी में रह रहा था लेकिन वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले का है।

अवैध रेत खनन में ‘सभी दलों के बड़े लोग शामिल’ हैं : जी. परमेश्वर

बेंगलूरु/भाषा। कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने रेत माफिया से घमकियां मिलने का एक महिला विधायक द्वारा दावा किये जाने के बाद, मंगलवार को कहा कि “सभी दलों के बड़े लोग” अवैध रेत खनन में शामिल हैं।

उन्हे प्रयासों के बाद उन्हें धमकियां मिल रही हैं। गृह मंत्री ने कहा कि यह एक ‘शर्मनाक स्थिति’ है।



वह विधानसभा में, देवदुर्ग से जद(एस) विधायक करेम्मा नायक द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

परमेश्वर ने रायचूर जिले में अवैध रेत खनन के बारे में कहा, “मैंने इस बारे में विवरण साझा नहीं किया है कि इसमें कौन-कौन शामिल है, इसका सरणन कौन है। यह एक बड़ा गिराह है। इसमें बड़े-बड़े लोग शामिल हैं। सभी पार्टियों के बड़े लोग इसमें शामिल हैं... यह थोड़ी

शर्मनाक स्थिति है।” उन्होंने कहा कि यह जल्द ही इस बात पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाएंगे कि पुलिस को इससे कैसे निपटना चाहिए। परमेश्वर ने कहा, “हम इस मामले में कोई नरमी नहीं बरतेंगे। मैं जिले के विधायकों की बैठक बुलाऊंगा और कोई भी निर्णय लेने से पहले उनके सुझाव लूंगा।”

सरकार गौमाता के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध

रायपुर/भाषा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि गौमाता के संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में गौमाता पर बनी पहली फिल्म- ‘गोदान’ का ‘ट्रैलर लॉन्च’ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गौमाता के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। गौमाता ना सिर्फ आध्यात्मिक रूप से पूजनीय हैं बल्कि गाय का आर्थिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है। साय ने फिल्म- ‘गोदान’ को छत्तीसगढ़ में कर मुक्त किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा, “छत्तीसगढ़ में गौ संवर्धन के लिए बहुत कार्य हो रहा है। गौशाला में गायों के चारे के बिना ही जाने वाली अनुदान राशि को 20 रुपये से बढ़ाकर 35 रुपये किया गया है साथ ही गौशाला को अब 25 लाख रुपये की सहायता राशि दी जा रही है।”



यूजीसी के नए नियम भेदभावपूर्ण नहीं होंगे, दुरुपयोग नहीं होगा : सरकार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/बरेली/भाषा। सरकार ने मंगलवार को जोर देकर कहा कि जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए नए यूजीसी नियमों का “दुरुपयोग” नहीं होने दिया जाएगा और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। वहीं, छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि ये नियम परिसरों में अराजकता पैदा कर सकते हैं।



कई राज्यों में इन नियमों के विरोध में छात्रों के प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आश्वासन दिया कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और नियमों का “दुरुपयोग” नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा, “मैं विनम्रतापूर्वक सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि किसी को भी किसी प्रकार के उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ेगा, कोई भेदभाव नहीं होगा और किसी को भी भेदभाव के नाम पर इस नियम का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा।” प्रधान ने कहा, “चाहे यूजीसी हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उनकी जिम्मेदारी है। मैं आश्वासन देता हूँ कि यह संविधान के दायरे में ही रहेगा।”

संयुक्त राष्ट्र को अब अंतरराष्ट्रीय शांति कायम करने वाली संस्था के रूप में नहीं देखा जाता : भारत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

संयुक्त राष्ट्र/भाषा। भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच भारत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को अब अंतरराष्ट्रीय शांति सुनिश्चित करने वाली संस्था के रूप में नहीं देखा जा रहा है और शांति एवं सुरक्षा से जुड़े परिणाम हासिल करने के लिए चर्चाएं “समानांतर बहुपक्षीय ढांचों” की ओर बढ़ गई हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने सोमवार को यहां ‘अंतरराष्ट्रीय कानून के शासन की पुनः पुष्टि: शांति, न्याय और बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करने के मार्ग’ विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस में कहा, “सार्वभौमिक सदस्यता वाले

सबसे शक्तिशाली अंग सुरक्षा परिषद की वैश्विक भू-राजनीतिक संघर्षों को रोकने और सुलझाने में लगातार विफलता सामने आ रही है। इसी पृष्ठभूमि में अमेरिकी



नरेन्द्र मोदी समेत कई वैश्विक नेताओं को अपने ‘शांति बोर्ड’ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। यह बोर्ड गाजा में स्थायी शांति लाने और वैश्विक संघर्षों को सुलझाने के लिए एक नए साहसपूर्ण तरीके पर काम करेगा। पिछले हफ्ते दावोस में विश्व

आर्थिक मंच (वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम) के मौके पर एक कार्यक्रम में, ट्रंप ने शांति बोर्ड के घोषणापत्र को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी। ट्रंप बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे, और जिन देशों ने इसके घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए हैं और इसमें शामिल हुए हैं, वे अर्जेंटीना, आर्मेनिया, अज़रबैजान, बहरीन, बुर्मारिया, हंगरी, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कोसोवो, मंगोलिया, मोरक्को, पाकिस्तान, पैराग्वे, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और उज़बेकिस्तान हैं। हरीश ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून के शासन का अनुप्रयोग निरंतरता, वस्तुनिष्ठता और पूर्वानुमेयता पर आधारित होना चाहिए तथा इसमें दोहरे मानदंड नहीं होने चाहिए।

भारत वैश्विक ऊर्जा वृद्धि का केंद्र है : सुल्तान अहमद अल जबेर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेतुल (दक्षिण गोवा)/भाषा। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के उद्योग मंत्री सुल्तान अहमद अल जबेर ने मंगलवार को कहा कि भारत ऊर्जा मांग की सबसे तेज एवं सबसे जटिल वृद्धि के दौर के केंद्र में मौजूद है जो उभरते बाजारों, कृत्रिम मेधा और ऊर्जा प्रणालियों के व्यापक बदलाव से प्रेरित है। भारत ऊर्जा सप्ताह (आईईडब्ल्यू) में यूईए के उद्योग एवं उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री तथा एडीएनओसी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सुल्तान अल जबेर



ने कहा कि विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में भारत, वैश्विक मांग को आकार देने वाली एक निर्णायक शक्ति बन गया है। अगले 15 वर्ष में भारत में हवाई यात्रा में 150 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, शहरी आबादी एक अरब के करीब पहुंच जाएगी और डेटा सेंटर की क्षमता 10 गुना बढ़ जाएगी। अल जबेर ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा बाजारों में मौजूदा अस्थिरता एक कहीं

बड़े संरचनात्मक बदलाव को छिपाती है, एक ऐसा बदलाव जो सावधानी बरतने के बजाय निर्णायक कार्रवाई से जुड़ा है। उन्होंने कहा, “वर्तमान उथल-पुथल के पीछे व्यापक बदलाव की एक बड़ी तरंग छिपी है। परिवर्तन का लाभ उन्हीं को मिलता है जो साहसपूर्वक आगे बढ़ते हैं, न कि उन लोगों को जो सुदृढ़ के शांत होने का इंतजार करते हैं।” ऊर्जा के क्षेत्र में आज की कहानी को, एशिया तथा भारत के नेतृत्व में उभरते बाजारों का उदय, कृत्रिम मेधा (एआई) की तेज वृद्धि एवं डिजिटल बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार, और ऊर्जा प्रणालियों का बदलाव परिभाषित करते हैं।

भारत का ऊर्जा क्षेत्र 500 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश के अवसर देता है: प्रधानमंत्री मोदी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को वैश्विक निवेशकों को भारत के बढ़ते ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि यह क्षेत्र 500 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश के अवसर प्रदान करता है। मोदी ने साथ ही इस बात पर जोर दिया कि देश जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा 'शोधन' केंद्र बन जाएगा।

'भारत ऊर्जा सप्ताह' (आईडब्ल्यू) 2026 को संबोधित करते हुए उन्होंने निवेशकों से शोधन (रिफाइनिंग), एलएनजी 'वैल्यू चेन' अवसरचना, सिटी गैस वितरण तथा तेल एवं गैस अन्वेषण जैसे क्षेत्रों में निवेश करने का



आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का लक्ष्य 2030 तक तेल एवं गैस क्षेत्र में 100 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करना है। तेल शोधन क्षमता को 26 करोड़ टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 30 करोड़ टन प्रति वर्ष किया जाएगा।

मोदी ने कहा, "ऊर्जा क्षेत्र हमारी आकांक्षाओं का केंद्र है। इसमें 500 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश के अवसर मौजूद हैं। इसलिए, मेरी अपील है कि भारत में

बनाओ, भारत में नवाचार करो, भारत के साथ विस्तार करो, भारत में निवेश करो।" उन्होंने बताया कि ऊर्जा क्षेत्र में भारत शीर्ष पांच निर्यातकों में से एक है।

प्रधानमंत्री ने कहा, "ऊर्जा क्षेत्र की बात करें तो ऊर्जा मूल्य मूल्य में निवेश के अपार अवसर मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, अन्वेषण क्षेत्र को ही देखें। भारत ने इसे काफी हद तक खोल दिया है।" उन्होंने कहा, "आप हमारे गहरे

समुद्र में अन्वेषण प्रयासों, 'समुद्र मंथन' परियोजना से भी अवगत हैं।" मोदी ने कहा, "हम इस दशक के अंत तक अपने तेल एवं गैस क्षेत्र में निवेश को बढ़ाकर 100 अरब अमेरिकी डॉलर करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य अन्वेषण के दायरे को 10 लाख वर्ग किलोमीटर तक विस्तारित करना भी है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यहां 170 से अधिक ब्लॉक आवंटित किए जा चुके हैं।" उन्होंने कहा कि अंडमान एवं निकोबार बेसिन भी देश की अगली हाइड्रोकार्बन उम्मीद के रूप में उभर रहा है।

मोदी ने अन्वेषण क्षेत्र में किए गए कई सुधारों पर भी चर्चा की और बताया कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में उल्लेखनीय कमी आई है। उन्होंने कहा, "आईडब्ल्यू के पिछले संस्करण में जो भी सुझाव दिए गए थे उनके अनुरूप हमने अपने

नियमों में बदलाव किए हैं। यदि आप अन्वेषण क्षेत्र में निवेश करते हैं, तो आपकी कंपनी की लाभप्रदता में निश्चित रूप से वृद्धि होगी।" उन्होंने कहा कि भारत की एक और विशेषता ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को अत्यधिक लाभदायक बनाती है। इसकी शोधन क्षमता बहुत अधिक है। शोधन क्षमता के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है।

प्रधानमंत्री ने कहा, "जल्द ही हम पहले स्थान पर होंगे। आज भारत की शोधन क्षमता लगभग 26 करोड़ टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) है। इसे बढ़ाकर 30 करोड़ टन प्रति वर्ष से अधिक करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। यह निवेशकों के लिए एक बड़ा लाभ है।" उन्होंने बताया कि भारत में एलएनजी की मांग लगातार बढ़ रही है। भारत ने अपनी कुल ऊर्जा मांग का 15 प्रतिशत एलएनजी से पूरा करने का

लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा, "इसलिए, हमें संपूर्ण एलएनजी मूल्य मूल्य पर काम करने की आवश्यकता है। भारत परिवहन पर भी बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। हम एलएनजी परिवहन के लिए आवश्यक जहाजों का विनिर्माण यहीं भारत में कर रहे हैं।" मोदी ने बताया कि हाल ही में भारत में जहाज निर्माण के लिए 70,000 करोड़ रूपए का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। उन्होंने साथ ही कहा कि भारत अब ऊर्जा सुरक्षा से आगे बढ़कर ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र परिवेश बना रहा है जो घरेलू मांग को पूरा कर सकता है और किराफायती शोधन एवं परिवहन समाधानों के साथ, विश्व को निर्यात को भी अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगा।

मुलाकात दक्षिण भारत राष्ट्रमत



राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में आदिवासी समुदायों के अतिथियों, झांकियों में शामिल कलाकारों और गणतंत्र दिवस परेड 2026 के अन्य प्रतिभागियों से मुलाकात की। उनके कार्यालय ने यह जानकारी दी। राष्ट्रपति कार्यालय ने मुलाकातों की तस्वीरें सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर साझा कीं। पोस्ट में कहा गया है, "राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आदिवासी समुदायों के अतिथियों, झांकी कलाकारों और डॉक्टर चालकों, एनएसएस (राष्ट्रीय सेवा योजना) के स्वयंसेवकों और एनसीसी (नेशनल कैडेट कोर) कैडेटों, अधिकारियों और गणतंत्र दिवस परेड 2026 के अन्य प्रतिभागियों से मुलाकात की।"

तेजी से निर्णय लेते हुए प्रौद्योगिकी को लागू करने वाला देश ही आगे रहता है : राजनाथ

नई दिल्ली/भाषा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया है कि स्वदेशी प्रणालियां देश की परिचालन तैयारियों को मजबूत कर रही हैं।



उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सोच बन चुकी आत्मनिर्भरता को हासिल करने में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना भी की। सिंह डीआरडीओ के एक कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में डीआरडीओ के वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ भी शामिल हुए, जो गणतंत्र दिवस परेड में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। सिंह ने कहा कि प्रौद्योगिकी तेजी से बदल रही है। उन्होंने कहा, "आज जो भी तकनीक नई है, वह चार-पांच साल में अप्रासंगिक हो सकती है। इसलिए, आज के समय में, विशेष रूप से युद्धक्षेत्र में, हमें केवल

'सर्वश्रेष्ठ की उत्तरजीविता' के सिद्धांत पर ध्यान देने के बजाय 'सबसे तेज और आगे रहने वालों के सफल होने' के सिद्धांत को भी ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए।

रक्षा मंत्री ने कहा, "जो देश तेजी से सोचता है, निर्णय लेता है और प्रौद्योगिकी को लागू करता है, वही आगे रहता है।" उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्धक्षेत्र में डीआरडीओ की तकनीक का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया और स्वदेशीकरण के प्रयासों के आधार पर रक्षा क्षेत्र में तेजी से हो रहे बदलावों में यह संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।



जो सरकार सनातन धर्म के अनुयायियों को निराश करती है, वह कमी सत्ता में वापस नहीं आएगी : शाह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अहमदाबाद/भाषा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि जो सरकार सनातन धर्म के मूल्यों को कायम रखने में विफल रहती है, वह कभी सत्ता में वापस नहीं आएगी।

गांधीनगर में स्वामीनारायण संप्रदाय की एक सभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि विभिन्न सनातन परंपराओं के अनुयायी स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक इस उम्मीद में इंतजार करते रहे कि उन्हें ऐसी सरकार मिलेगी, जो सनातन धर्म को उचित महत्व देगी और इसके

सिद्धांतों के अनुसार शासन करेगी। उन्होंने कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि सत्ता के आशीर्वाद से, सनातन धर्म के अनुयायियों को निराश करने वाली कोई भी सरकार इस देश में फिर कभी सत्ता में नहीं आएगी।"

आयोजन भगवान स्वामी नारायण द्वारा 1826 में लिखित 212 संस्कृत श्लोकों वाली पवित्र आचार संहिता 'शिक्षापत्री' के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। यह स्वामी नारायण संप्रदाय के अनुयायियों के लिए एक मूलभूत मानवदर्शन के रूप में कार्य करती है, जिसमें अहिंसा, पवित्रता, आचार और दैनिक कर्तव्यों सहित नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों की रूपरेखा दी गई है।

मोदी सरकार के आर्थिक विकास के आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवाल : कांग्रेस



दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस ने देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति और बढ़ती असमानता को चिंताजनक करार देते हुए मंगलवार को दावा किया कि सरकार के आर्थिक विकास के आंकड़ों की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में आ गई है। कांग्रेस के शोध विभाग के प्रमुख राजीव गोड़ा और पार्टी के संचार विभाग के शोध मामले के प्रभारी अमिताभ दुबे ने अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर एक पुस्तिका जारी की और कहा कि देश को आज सुविधियों की नहीं, ईमानदार आंकड़ों की जरूरत है।

रिपोर्ट जारी करते हुए गोड़ा ने कहा: अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति मोदी सरकार की प्राथमिकताओं को उजागर करती है। ऐसे समय में जब असमानता बढ़

से बढ़तर हो रही है, कॉर्पोरेट मुनाफा बढ़ रहा है, सार्थक रोजगार सृजन नहीं हो रहा है, तो मोदी सरकार कल्याण में कटौती करने पर अड़ी हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एक बयान का हवाला देते हुए कहा, यह सरकार गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं - चार जातियों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवच को खत्म कर रही है।

इसके अलावा, भारत के डेटा की विश्वसनीयता पर व्यापक रूप से सवाल उठाए जा रहे हैं। भारत को ईमानदार आंकड़ों की जरूरत है और एक समावेशी विकास मॉडल जो रोजगार पैदा करता है, न कि केवल सुविधियां। मोदी सरकार का प्रचार हमें पूर्ववर्ती एनडीए सरकार के 'भारत उदय' वाले अहंकार की याद दिलाता है। अमिताभ दुबे ने कहा, जिस विकास से केवल कुछ लोगों को लाभ होता है, वह सफलता नहीं है। यह एक बेतुानी संकेत है। बढ़ती असमानता और सिमटता जन कल्याण बड़े पैमाने पर आर्थिक कुप्रबंधन के स्पष्ट संकेतक हैं। लेकिन मूल रूप से अच्छी नीति ईमानदार डेटा से शुरू होती है। उन्होंने कहा, हम सरकार से देश के सामने वास्तविक आंकड़े रखने के लिए कहते हैं, न कि लोगों को गुमराह करने वाले हेरफेर किए गए आंकड़े।

वाईएसआरसीपी का आरोप : 'मुफ्त रेत' नीति से सत्तारूढ़ पार्टी के नेता अवैध खनन कर रहे



अमरावती/भाषा। युवजन श्रमिक रायचू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के वरिष्ठ नेता के गोवर्धन रेड्डी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश की 'मुफ्त रेत नीति' की वजह से सत्तारूढ़ दल के नेता बड़े पैमाने पर अवैध खनन कर रहे हैं जिससे राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की लूट हो रही है।

रेड्डी ने दावा किया इसे 'मुफ्त रेत' पहल के रूप में पेश किया गया था, लेकिन सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से पांच गुना से अधिक कीमत पर रेत बेची जा रही है। रेड्डी ने एक प्रेस विज्ञापन में आरोप लगाया, गठबंधन सरकार की बहुचर्चित 'मुफ्त रेत' नीति

पूरी तरह से धोखा है। यह सत्ताधारी दल के नेताओं द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध खनन और प्राकृतिक संसाधनों की संगठित लूट का बहाना बन गई है।

उनके अनुसार, सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के विधायक कथित तौर पर प्रत्येक रेतोले क्षेत्र से प्रति माह तीन करोड़ रूपए से अधिक की कमाई कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये गतिविधियां स्थापित नियमों, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों और पर्यावरण सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करते हुए की जा रही हैं।

वाईएसआरसीपी की पूर्व सरकार ने विनियमित रेत निविदाओं से सरकारी खजाने के लिए सालाना लगभग 700 करोड़ रूपए का राजस्व हासिल किया था, जो 2019 से 2024 के बीच लगभग 3,500 करोड़ रूपए तक पहुंच गया था।

न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया जारी, जांच समिति की रिपोर्ट का इंतजार : रीजीजू

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। संसदीय कार्य मंत्री किरन रीजीजू ने मंगलवार को कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया जारी है और सरकार उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

बिरला ने न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने के लिए बहुदलीय नोटिस स्वीकार करने के बाद पिछले साल 12 अगस्त को उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए समिति का गठन किया था। न्यायमूर्ति को 14 मार्च को दिल्ली उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में तब वापस भेज दिया गया था, जब उनके आधिकारिक आवास पर नोटों के जले हुए बंडल मिले थे। यह पूछे जाने पर कि क्या बुधवार से शुरू होने वाले संसद के आगामी बजट



अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिकता वी वी आचार्य शामिल हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और बर्खास्तगी की प्रक्रिया से परिचित अधिकारियों ने बताया कि संसद के किसी भी सदन में सांसदों के सामने अपना पक्ष रखते हुए न्यायमूर्ति वर्मा यह घोषणा कर सकते हैं कि वह पद छोड़ रहे हैं और उनके मौखिक बयान को उनका इस्तीफा माना जाएगा। यदि न्यायमूर्ति वर्मा इस्तीफा देने का निर्णय लेते हैं, तो वह उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को मिलने वाली पेंशन और अन्य लाभों के हकदार होंगे।

विपक्ष ने वीबी-जी राम जी और एसआईआर पर चर्चा की मांग की, सरकार ने कहा : 'रिवर्स गियर' में नहीं जा सकते

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। सरकार ने बुधवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के दौरान 'विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम' तथा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चर्चा की विपक्ष की मांग को मंगलवार को अस्वीकार कर दिया और कहा कि दोनों विषय पर पहले चर्चा हो चुकी है तथा अब "हम रिवर्स गियर में नहीं जा सकते।"

बजट सत्र से एक दिन पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने इन दोनों विषयों पर चर्चा की मांग उठाई। बैठक के दौरान, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और माकपा सांसद जॉन बिट्टास सहित कई विपक्षी सदस्यों ने सत्र के लिए सरकार को



कामकाज का एजेंडा सामने नहीं रखे जाने पर आपत्ति जताई, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री किरन रीजीजू ने कहा कि यह उचित समय पर चर्चा के लिए विपक्ष की मांग पर मंत्री ने कहा, "एक बार जब कोई कानून देश के सामने आ जाता है, तो हमें उसका पालन करना होता है। हम रिवर्स गियर में वापस नहीं जा सकते।" उन्होंने कहा कि विपक्षी सांसदों ने कई मुद्दे रखे हैं और इन्हें राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट पर चर्चा के दौरान उठाया जा

सकता है। कुछ विपक्षी नेताओं द्वारा सत्र के लिए विधायी एजेंडा साझा नहीं किए जाने की शिकायत के बाद रीजीजू ने कहा, "यह साल का पहला सत्र है। आम तौर पर, सरकारी कामकाज की सूची राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद साझा की जाती है। हालांकि, मैं सूची साझा करने के लिए तैयार हूं, मैंने अधिकारियों को ऐसा करने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा कि यह कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है और सदन को सुचारु रूप से चलाने पर ध्यान केंद्रित है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर चर्चा की मांग पर एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "संसद के दोनों सदनो में पिछले सत्र में चुनाव सुधारों पर व्यापक चर्चा हुई थी, जहां विपक्ष ने भी यह मुद्दा उठाया था। अगर एक और बहस की मांग की जाती है तो यह अनुचित है।"

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्कूल बस पलटी, छह छात्रों समेत 10 लोग घायल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

शिमला/भाषा। कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर उपमंडल में मंगलवार को

एक निजी स्कूल बस पलट गई जिससे छह छात्रों समेत कम से कम 10 लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, शिवनगर के पास लाहट-शिवनगर लिंक रोड पर हुए इस हादसे में छह

बच्चे, दो शिक्षक, बस चालक और परिचालक घायल हो गए। पुलिस की एक टीम ने घायलों को बस से निकाला और उन्हें पानुमपुर सिविल अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि जांच की जा रही है।

निवेश के अभाव में वैश्विक तेल उत्पादन में आठ प्रतिशत की गिरावट का जोखिम : पुरी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बैतूल (गोवा)/भाषा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 के उद्घाटन समारोह के दौरान कहा कि अगर मौजूदा तेल और गैस उत्पादन में निवेश बंद हो जाता है तो आगले दशक में वैश्विक तेल उत्पादन में सालाना लगभग आठ प्रतिशत की गिरावट आ सकती है। यह ब्राजील और नॉर्वे के संयुक्त

वार्षिक उत्पादन के बराबर है। पुरी ने कहा कि भले ही नवीकरणीय ऊर्जा ने तेजी से विस्तार किया है और अब वैश्विक बिजली उत्पादन का लगभग एक-तिहाई हिस्सा है, लेकिन वैश्विक ऊर्जा बदलाव केवल प्रतिस्थापन पर आधारित नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, ऊर्जा का इतिहास कभी भी केवल प्रतिस्थापन के बारे में नहीं रहा। यह हमेशा वृद्धि और नए स्रोत जोड़ने के बारे में रहा है। मंत्री ने यह भी कहा कि ऊर्जा बदलाव, ऊर्जा सुरक्षा और प्रणाली की मजबूती को एक साथ आगे



बढ़ाना होगा ताकि बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा किया जा सके। पुरी ने कहा कि पिछले एक दशक में नवीकरणीय ऊर्जा तेजी

से बढ़ी है। उन्होंने कहा कि वैश्विक बिजली उत्पादन में रफ़्तक ऊर्जा की हिस्सेदारी कम होती लागत और नीतिगत उपायों के कारण लगभग पांचवें से बढ़कर लगभग एक तिहाई हो गई है। पुरी ने कहा, फिर भी पारंपरिक ऊर्जा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने बताया कि अगर मौजूदा तेल और गैस उत्पादन में निवेश आज बंद हो जाए, तो आगले दशक में वैश्विक तेल उत्पादन में सालाना लगभग आठ प्रतिशत की गिरावट आएगी, जो हर साल ब्राजील और नॉर्वे के

संयुक्त वार्षिक उत्पादन से अधिक के नुकसान के बराबर है। पुरी ने कहा कि नए ऊर्जा स्रोत हमेशा से मौजूदा स्रोतों को पूरा करते रहे हैं, जिससे ऊर्जा प्रणाली को विस्तार और अनुकूलन करने का मौका मिलता है। यह वैश्विक ऊर्जा बदलाव परिभाषित वास्तविकता बनी हुई है। पुरी ने कहा कि पिछले एक साल में वैश्विक ऊर्जा प्रणाली पर दबाव तेज हो गया है और ऊर्जा व्यवस्था जटिल तरीकों से विकसित हो रही है।

अदाणी समूह, एम्ब्रेयर भारत में क्षेत्रीय विमान विनिर्माण संयंत्र करेंगे स्थापित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। अदाणी समूह और ब्राजील की प्रमुख वैमानिकी कंपनी एम्ब्रेयर ने एक रणनीतिक सहयोग की मंगलवार को घोषणा की। इसका मकसद भारत में एक क्षेत्रीय विमान विनिर्माण संयंत्र स्थापित करना है जो देश की स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते नागर विमान बाजारों में से एक है। यह साझेदारी छोटे व मझोले शहरों के लिए एवआई संपर्क को बेहतर बनाने में मदद करेगी। अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस और एम्ब्रेयर के अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजधानी में नागर विमानन मंत्रालय में मंगलवार को आयोजित एक समारोह में भारत



में क्षेत्रीय परिवहन विमानों पर रणनीतिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोनों कंपनियां देश में क्षेत्रीय परिवहन विमानों के लिए एक 'फाइनल असेंबली लाइन' (एफएएल) भी स्थापित करेंगी। अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस के निदेशक जीत अदाणी ने कहा कि एम्ब्रेयर के साथ सहयोग से भारत में एक क्षेत्रीय विमान विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। एम्ब्रेयर 150 सीट तक के

वाणिज्यिक विमान बनाती है। स्थान और प्रस्तावित सुविधा के रथान से जुड़े विवरण साझा नहीं किए गए। नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने कहा कि यह सहयोग केवल क्षेत्रीय विमानों के संयोजन तक ही सीमित नहीं है। इसमें प्राविशिल प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल विकास, सुदृढ़ आपूर्ति मूल्य और भारत को क्षेत्रीय विमानों का एक विश्वसनीय विनिर्माण केंद्र बनाना भी शामिल है।



अच्छा इंसान बनने की कोशिश उसी तरह करो जिस तरह हम सुंदर बनने की करते हैं।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

यूजीसी नियम: अविश्वास की दीवार न बनाएं

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में जातिगत भेदभाव को रोकने और समानता को बढ़ावा देने के लिए लागू किए गए नियमों ने कई आशंकाएं पैदा कर दी हैं। अभी ये नियम ही पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं। उनकी कई तरह से व्याख्या की जा रही है। अगर समता समिति में एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और महिला के साथ सामान्य वर्ग का अनिवार्य प्रतिनिधित्व होता तो आज सड़कों पर इतना आक्रोश न होता। सामान्य वर्ग के लोग यह सोचने को मजबूर हैं कि हमारे बच्चों को पहले ही शक के दायरे में ले लिया गया है। देश में जातिगत भेदभाव एक कड़वी सच्चाई है। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। हालांकि इसमें बहुत कमी आई है। जो व्यक्ति इसका पीड़ित है, उसे न्याय मिलना चाहिए, लेकिन इस प्रणाली में किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। नियम ऐसे हों जो भेदभाव को खत्म करें, सामाजिक समरसता को बढ़ावा दें। यूजीसी के उक्त नियम सभी वर्गों का विश्वास जीतने में कहीं-न-कहीं विफल रहे हैं। आंदोलन कर रहे लोग यह नहीं कह रहे कि नियम लागू न किए जाएं। बेशक नियम लागू करें, लेकिन सबको अनिवार्य प्रतिनिधित्व देने के साथ उनकी आशंकाओं का निवारण करें। किसी भी नियम-कानून को लागू करने से पहले उसके दूसरे पहलू को जरूर देखना चाहिए। कहीं उसका दुरुपयोग तो नहीं होगा? कहीं यह निर्दोष के लिए फांसी का फंदा तो नहीं बन जाएगा? ध्यान रहे, पूर्व में दहेज प्रथा और जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए संसद ने जो कानून बनाए थे, उनका बहुत दुरुपयोग हुआ है। उन पर उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने चिंता जताई है। फर्जी मुकदमों के कारण हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई है।

सामान्य वर्ग की एक चिंता यह है कि अब उच्च शिक्षण संस्थानों में उनके बच्चों को बेवजह निशाना बनाया जाएगा। झूठी शिकायतों की रोकथाम के लिए कोई पुख्ता व्यवस्था न होने से संस्थान जातिगत झगड़ों के मैदान बन सकते हैं। जो उच्च पढ़ाई-लिखाई और नए दोस्त बनाने की होती है, उसमें बड़े डर के साप में रहेंगे। इन नियमों से समरसता कितनी बढ़ेगी, यह बहुत का विषय हो सकता है, लेकिन कई अभिभावक अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए यह जरूर कहेंगे कि वे बहुत सोच-समझकर ही किसी से दोस्ती करें। बच्चे भी अन्य वर्ग के सहपाठियों से बातचीत करने से कतराएंगे। क्या इससे समावेशी समाज का निर्माण होगा? विद्यार्थी जीवन में प्रतिस्पर्द्धा की भावना होती है। कक्षा में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चे से कुछ सहपाठियों को ईर्ष्या हो सकती है। अगर सामान्य वर्ग के किसी प्रतिभावान विद्यार्थी के खिलाफ झूठी शिकायत कर दी जाए तो क्या होगा? संस्थान तो खुद को बचाने के लिए कार्रवाई करेगा। उस विद्यार्थी का भविष्य चौपट हो जाएगा। अगर वह बाद में निर्दोष साबित हो जाए तो यह राहत काफी नहीं होगी, क्योंकि इस दौरान उसे जो मानसिक पीड़ा होगी, पढ़ाई का नुकसान होगा, छवि पर दाग लगेगा, उसकी भरपूरी कोई नहीं कर सकेगा। कौन माता-पिता चाहेंगे कि उनकी प्रतिभावान संतानें पढ़ाई करने जाएं और पेशी भुगतें? ऐसी स्थिति में साधन संपन्न लोग अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहेंगे, जिससे प्रतिभा पलायन होगा। क्या इससे हम विश्वगुरु बनेंगे? जब एक पक्ष के पास असौमित्र अधिकार हों, उसे दंड का कोई भय न रहे तो भविष्य में विवाद कम नहीं होंगे, बल्कि बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। यूजीसी के नियमों के जरिए उच्च शिक्षण संस्थानों में हर विद्यार्थी को संरक्षण दिया जाए। किसी के साथ भेदभाव न हो। कोई भी खुद को पराया न समझे। यही सच्चा सामाजिक न्याय होगा।

ट्वीटर टॉक



डबल इंजन सरकार की अभिनव पहल! 'पंच गौरव कार्यक्रम' प्रदेश के हर जिले की विशिष्ट पहचान को नई उड़ान दे रहा है। एक उत्पाद, एक उपज, एक खेल, एक वनस्पति और एक पर्यटन स्थल स्थानीय क्षमताओं को वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है।

-भजनलाल शर्मा

पीयूष पांडे जी भारतीय विज्ञापन जगत के प्रतिष्ठित और प्रभावशाली रचनाकार रहे हैं, जिनका सृजनात्मक करियर चार दशकों से अधिक समय तक फैला रहा। विज्ञापन अभियानों के माध्यम से उन्होंने न केवल उद्योग में रचनात्मक परिवर्तन किए।

-दिया कुमारी



आज छोटी खाटू में आचार्य महाश्रमण मर्यादा महोत्सव में हिस्सा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैन धर्म अहिंसा पर आधारित है। किसी भी जीव, किसी भी प्राणी के जीवन को नुकसान पहुंचाना हिंसा मानी गई है। लेकिन हथियार से हिंसा करना या किसी को मारना-पीटना ही हिंसा नहीं है।

-वसुंधरा राजे

प्रेरक प्रसंग

मानवता का सम्मान

नेपोलियन बोनापार्ट अपने विजय अभियानों के दौरान जीते हुए राज्यों को, विजित राजाओं से उनके यकादर रहने का आश्वासन प्राप्त करने के बाद उन्हें पुनः लौटाना करता था। एक बार, ऐसे ही एक हारे हुए राजा को नेपोलियन ने उसका राज्य वापस दे दिया, लेकिन वह शत्रुओं से जा मिला और नेपोलियन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। नेपोलियन ने क्रोधित होकर उसकी राजधानी पर आक्रमण कर दिया। नेपोलियन की विशाल सेना से भयभीत होकर राजा अपने परिवार के साथ जंगलों में भाग गया, लेकिन जल्दबाजी में एक बीमार राजकुमार महल में ही छूट गया। नेपोलियन ने राजमहल को तोप से उड़ाने का आदेश दिया। लोगों की गरज के बीच, बीमार राजकुमार इधर-उधर दौड़ने लगा। किसी तरह सिपाहियों ने यह सूचना नेपोलियन तक पहुंचाई। यह सुनते ही नेपोलियन ने तुरंत गोलाबारी रुकवा दी। तोपें शांत होते ही सेनापति नेपोलियन के पास आया और बोला, 'यह आपने क्या किया? सारे सैनिकों का उत्साह भंग हो गया है और सैनिकों के नियमों का भी उल्लंघन हुआ है।' यह सुनकर नेपोलियन ने उत्तर दिया, 'मेरे भाई, मैं मानता हूँ कि सैनिकों के नियमों का उल्लंघन हुआ है, लेकिन साथ ही मानवता का अपमान भी हुआ होता, और यह हम वीरों को शोभा नहीं देता।'

महत्वपूर्ण

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kammani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006. Editor : Bhupendra Kumar (Responsible for selection of news under PRB Act.) Group Editor - Shreekant Parashar. Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.Regn No.RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वार्निकल, टैंडर एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्तरावर्ती की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पुरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकाना को पाठक किसी भी रूप में उत्तरवाही नहीं बना सकता। - दक्षिण भारत राष्ट्रमत

सामयिक

नफरत बनाम संविधान : लोकतंत्र की असली कसौटी

नृपेन्द्र अभिषेक 'नृप'

आधुनिक लोकतंत्रों के सामने नफरती भाषण की समस्या एक गंभीर और बढ़ती हुई चुनौती बनती जा रही है, विशेषकर भारत जैसे बहुलतावादी समाज में, जहाँ धर्म, जाति, भाषा और विचारधाराओं की विविधता ही सामाजिक ढाँचे की आधारशिला है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक विमर्श का उद्देश्य आदर्श रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करना होना चाहिए, किंतु दुर्भाग्यवश यह विमर्श कई बार उकसावेपूर्ण और विभाजनकारी भाषा में बदल जाता है। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा नफरती भाषण और उस पर प्रतिक्रिया देने वालों की जिम्मेदारी को लेकर की गई हालिया टिप्पणियों ने इस संवेदनशील विषय को एक बार फिर सार्वजनिक बहस के केंद्र में ला दिया है। न्यायालय की ये टिप्पणियाँ एक गहरी संवैधानिक चिंता को उजागर करती हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुँचाने वाले भाषण के लिए ढाल नहीं बनाया जा सकता और न ही चुनिंदा आक्रोश को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

नफरती भाषण केवल आपत्तिजनक शब्दों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह ऐसी भाषा होती है जो किसी व्यक्ति या समुदाय को अमानवीय बनाती है, उसे हाशिये पर धकेलती है या उसके विरुद्ध शत्रुता और घृणा को बढ़ावा देती है। भारत जैसे सामाजिक रूप से जटिल देश में इस प्रकार का भाषण सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने और पहले से मौजूद सामाजिक दरारों को और गहरा करने की क्षमता रखता है। मद्रास उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब मूल नफरती भाषण पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तो उस पर प्रतिक्रिया देने वालों को अपराधी ठहराना न्यायसंगत नहीं है। यह टिप्पणी कानून के क्रियान्वयन और राजनीतिक जवाबदेही में मौजूद एक गंभीर असंगति को उजागर करती है। जब सत्ता में बैठे लोग भड़काऊ बयान देकर भी दंड से बच जाते हैं, तो यह संशय जाता है कि सत्ता उन्हें विशेष संरक्षण देती है, जिससे संस्थानों में जनता का विश्वास कमजोर होता है।

एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता द्वारा किसी धार्मिक आस्था के विरुद्ध की गई टिप्पणी से जुड़ा विवाद इस बात का उदाहरण है कि राजनीतिक भाषण किस प्रकार संवैधानिक सीमाओं को पार कर सकता है। यद्यपि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, लेकिन यह अधिकार पूर्ण



समाज की सामूहिक भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। नागरिक समाज, मीडिया और आम जनता को मिलकर नफरत से प्रेरित कथाओं को अस्वीकार करना होगा। आज के डिजिटल युग में, विशेषकर सोशल मीडिया के माध्यम से, कोई भी बयान पलक झपकते ही व्यापक प्रभाव डाल सकता है।

नहीं है और इस पर युक्तिसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, विशेषकर तब जब कोई भाषण सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के लिए खतरा बन जाए। न्यायालय की चिंता केवल उस बयान तक सीमित नहीं थी, बल्कि इस तथ्य पर भी केंद्रित थी कि राज्य ने मूल वक्ता के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि प्रतिक्रिया देने वालों के खिलाफ कानूनी कदम उठाए गए। कानून का ऐसा वयनात्मक प्रयोग संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है।

राजनीतिक नेताओं पर सामान्य नागरिकों की तुलना में कहीं अधिक नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी होती है। उनके शब्दों में सत्ता का वजन होता है, वे जनमानस को प्रभावित करते हैं और कई बार पूर्वाग्रह को वैधता प्रदान कर देते हैं। जब नेता स्वयं नफरती भाषा का प्रयोग करते हैं, तो इससे असहिष्णुता सामान्य हो जाती है और समाज में घर्षणशील तत्वों को प्रोत्साहन मिलता है। मद्रास उच्च न्यायालय ने सही ही कहा कि प्रतिक्रिया को दबाना और मूल कारण को अनदेखा करना न्याय की अवधारणा के साथ अन्याय है। कोई भी लोकतंत्र उस स्थिति में स्वस्थ रूप से कार्य नहीं कर सकता, जहाँ असमंजस को दंडित किया जाए और उकसावे को राजनीतिक सुविधा के कारण संरक्षण दिया जाए।

न्यायालय द्वारा रेखांकित किया गया एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सुधार या वैचारिक आलोचना के नाम पर पूरे समुदाय को निशाना बनाने का खतरा। प्रगतिशील समाज में धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं की ताकिक आलोचना आवश्यक है, किंतु यह आलोचना संवेदनशीलता और सम्मान के साथ होनी चाहिए। किसी पूरे समुदाय को पिछड़ा, खतरनाक या समस्या का स्रोत बनाना सामूहिक दोषारोपण है, जो नफरती भाषण का मूल तत्व होता है। सुधारात्मक विमर्श का उद्देश्य संवाद और समझ को बढ़ाना होना चाहिए, न कि अपमान और उकसावे को। राजनीतिक लाभ के लिए पहचान की राजनीति को हथियार बनाने की प्रवृत्ति अत्यंत चिंताजनक है। नफरती भाषण अक्सर भावनाओं को भड़काकर समर्थन जुटाने का एक आसान तरीका बन जाता है, जहाँ तर्क और विवेक की जगह भय और आक्रोश को प्राथमिकता दी जाती है। यह रणनीति भले ही अल्पकालिक चुनावी लाभ दे दे, लेकिन इससे सामाजिक एकता को दीर्घकालिक क्षति पहुँचती है। न्यायालय की टिप्पणियाँ इस बात की याद दिलाती हैं कि लोकतंत्र बहस से फलता-फूलता है, न कि दानवीकरण से। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा संविधानिक मूल्यों की कीमत पर नहीं होनी चाहिए।

ऐसे मामलों में न्यायपालिका की भूमिका

नजरिया

सड़कें बन रही सुरक्षित कम, जानलेवा ज्यादा

देवेन्द्र सिंह

मोबाइल : 80946 61100

हाल ही में जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में हर साल लाखों लोग सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवा रहे हैं और इनमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी कार दुर्घटनाओं की है। तेज रफ्तार, नियमों की अनदेखी और लापरवाह ड्राइविंग ने सड़कों को मौत का कुआं बना दिया है। दुनिया भर में सड़क सुरक्षा आज एक गंभीर वैश्विक चुनौती बन चुकी है। दुनिया में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं वाले शीर्ष 5 देशों में भारत, चीन, अमेरिका, ब्राजील और रूस शामिल हैं। इन देशों में खराब सड़क बुनियादी ढाँचे, तेज गति, यातायात नियमों की अनदेखी और अधिक जनसंख्या के कारण सड़क हादसों और मौतों की दर सबसे अधिक है, जहाँ भारत में हर 4 मिनट में एक व्यक्ति की जान चली जाती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि व्यापक और सतत जागरूकता अभियान नहीं चलाए गए, तो आने वाले वर्षों में यह संकट और गहराता जाएगा।

वैश्विक स्तर पर देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 2024 में सबसे अधिक, यानी 1.9 मिलियन से ज्यादा कार दुर्घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें 36 हजार से अधिक लोगों की मौत और 2.7 मिलियन से अधिक लोग घायल हुए। प्रति मिलियन आबादी पर औसतन 5,938 दुर्घटनाएं हुईं। अमेरिका में जागरूकता अभियान चलने के बावजूद दुर्घटनाओं का ग्राफ नीचे नहीं आ पा रहा और कार दुर्घटनाएं एक गंभीर समस्या बनी हुई हैं। विश्व के शीर्ष पांच देशों में जहां सड़क हादसे सबसे अधिक होते हैं, उनमें भारत, चीन, अमेरिका, ब्राजील और रूस शामिल हैं। खराब सड़क डिजाइन, तेज गति, बढ़ती आबादी और यातायात नियमों की अनदेखी इन देशों में मौतों की बड़ी वजह बन रही है।

भारत की स्थिति वैश्विक परिदृश्य में सबसे अधिक चिंताजनक है। विश्व की केवल 1 प्रतिशत कारें भारत में हैं, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली कुल मौतों का लगभग 11 प्रतिशत हिस्सा यहीं दर्ज होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सड़क हादसों से होने वाली मौतों के मामले में भारत पहले स्थान पर है। हर वर्ष करीब साढ़े चार लाख दुर्घटनाएं होती हैं और औसतन हर तीन से चार मिनट में एक व्यक्ति सड़क पर दम तोड़ देता है। यह केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि हर बार किसी घर का उजड़ जाना, किसी परिवार का सहारा छिन जाना है। सबसे दुखद तथ्य यह है कि सड़क दुर्घटनाओं



में जान गंवाने वालों में सबसे बड़ी संख्या 18 से 35 वर्ष के युवाओं की है। यही वह वर्ग है जिसे देश की सबसे सक्रिय, ऊर्जावान और उत्पादक आबादी माना जाता है। सड़क हादसे न केवल परिवारों को तोड़ते हैं, बल्कि देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति पर भी गहरा असर डालते हैं। एक युवा की मौत का मतलब केवल एक जान का जाना नहीं, बल्कि वर्षों की संभावनाओं का समाप्त हो जाना है। सरकारी आंकड़े इस संकट की गंभीरता को और स्पष्ट करते हैं। वर्ष 2023 में देश में लगभग 4.8 लाख सड़क दुर्घटनाएं दर्ज हुईं, जिनमें 1.72 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई। 2024 में यह आंकड़ा और बढ़कर 1.77 लाख मौतों तक पहुंच गया, यानी हर दिन औसतन 485 लोगों की जान गई। राष्ट्रीय राजमार्ग, जो देश के कुल सड़क नेटवर्क का मात्र 2 प्रतिशत हैं, उन पर 31 प्रतिशत मौतें दर्ज की गईं। ताज़ा आंकड़े 2024 में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 52,609 (लगभग 317 हिस्सा) लोग मारे गए। 2025 के पहले 6 महीनों में 26,770 से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं। यह तथ्य बताता है कि बेहतर और चौड़ी सड़कें जहां सुविधा देती हैं, वहीं तेज रफ्तार को भी बढ़ावा देती हैं। आंकड़ों पर नजर डाले तो 587 से अधिक मौतें ओवर स्पीड के कारण होती हैं।

राज्यवार स्थिति पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक सड़क दुर्घटनाओं में मौतों के लिहाज से लगातार शीर्ष पर बने हुए हैं। हादसों की संख्या के

मामले में तमिलनाडु सबसे आगे है, लेकिन बीते साल में मौतों की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दर्ज की गई। सड़क हादसों में हुई मौतों के मामले में यूपी दुनिया के कई देशों को पीछे छोड़ता है। इंटीग्रेटेड ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एनुकेशन (खट्क) की रिपोर्ट के अनुसार, यूपी में हर साल करीब 24 हजार लोग अपनी जान गंवाते हैं। प्रतिदिन हुई मौतों के लिहाज से देखें तो यह संख्या 65 के आसपास आती है। तमिलनाडू में हादसों की संख्या करीब 14 फीसदी के करीब, मध्यप्रदेश में 11.8 फीसदी, केरल में 9.5 फीसदी और उत्तर प्रदेश में 9 फीसदी है। जबकि मौत के मामले में उत्तरप्रदेश 14 फीसदी है। उसके बाद में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक आते हैं।

राजस्थान की तस्वीर भी कम भयावह नहीं है। कुल सड़क नेटवर्क में राज्य की हिस्सेदारी भले ही 3.4 प्रतिशत हो, लेकिन घातक दुर्घटनाओं में इसका अनुपात कहीं अधिक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान सड़क दुर्घटनाओं के मामले में देश में सातवें और मौतों के मामले में छठे पायदान पर है। प्रदेश में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में दस हजार से अधिक लोग अपनी जान गंवां देते हैं। 2023 के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में प्रतिदिन 30 से अधिक मौतें सड़क हादसों में हो रही हैं। हर साल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सात हजार से अधिक दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें चार हजार से ज्यादा लोगों की जान गई। विशेषज्ञों के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में मौतों की

अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, विशेषकर तब जब कार्यपालिका निष्पक्षता से कार्य करने में विफल रहती है। नफरती भाषण के विरुद्ध कार्रवाई न होने पर चिंता व्यक्त करके मद्रास उच्च न्यायालय ने संवैधानिक नैतिकता के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया है। जब राजनीतिक विमर्श लोकतांत्रिक मानदंडों को कमजोर करने लगे, तब न्यायालय मूक दर्शक नहीं बन सकता। हालांकि, न्यायिक हस्तक्षेप का उद्देश्य राजनीतिक जिम्मेदारी का स्थान लेना नहीं, बल्कि उसे सुनिश्चित करना होना चाहिए। इस पूरे प्रकरण से एक महत्वपूर्ण सबक यह मिलता है कि कानून के मानक एकसमान होने चाहिए। नफरती भाषण से संबंधित कानूनों को वक्ता की हैसियत या राजनीतिक संबद्धता की परवाह किए बिना समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। जब कानून का प्रवर्तन पक्षपातपूर्ण प्रतीत होता है, तो इससे असंतोष और अविश्वास जन्म लेता है, और कानूनी व्यवस्था की वैधता पर प्रश्नचिह्न लग जाता है। नागरिकों को लगने लगता है कि न्याय चयनित लोगों के लिए है, जिससे लोकतांत्रिक ताने-बाने को गहरी चोट पहुँचती है। न्यायालय की टिप्पणियाँ राजनीतिक वर्ग और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए आत्ममंथन का आह्वान हैं।

समाज की सामूहिक भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। नागरिक समाज, मीडिया और आम जनता को मिलकर नफरत से प्रेरित कथाओं को अस्वीकार करना होगा। आज के डिजिटल युग में, विशेषकर सोशल मीडिया के माध्यम से, कोई भी बयान पलक झपकते ही व्यापक प्रभाव डाल सकता है। ऐसे में जिम्मेदार संवाद की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ जाती है। यद्यपि कानूनी उपाय आवश्यक हैं, लेकिन सामाजिक स्तर पर नफरती भाषण की निंदा करना भी उसे हतोत्साहित करने का एक प्रभावी साधन है। नफरती भाषण को लेकर मद्रास उच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ राजनीतिक जीवन में विभाजनकारी भाषा के सामान्यीकरण के विरुद्ध एक समयोचित चेतावनी हैं। लोकतंत्र केवल चुनावों से जीवित नहीं रहता, बल्कि आपसी सम्मान, संवैधानिक अनुशासन और नैतिक संयम से फलता-फूलता है। राजनीतिक नेताओं को यह समझना होगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ दूसरों का हादत करने की छूट नहीं है। सच्चा नेतृत्व समाज को जोड़ने में है, न कि वैचारिक या चुनावी लाभ के लिए उसे बाँटने में। यदि भारत को एक जीवंत, समावेशी और सशक्त लोकतंत्र बने रहना है, तो नफरती भाषण का सामना दृढ़ता, निष्पक्षता और निरंतरता के साथ करना होगा और इसकी शुरुआत उन्होंने लोगों से होनी चाहिए, जिनके पास समाज की सोच को दिशा देने की सबसे अधिक शक्ति है।

बड़ी वजह तेज गति है। बेहतर महमल जैसी सड़कें और लंबे, सीधे हाईवे वाहन चालकों को तेज रफ्तार से वाहन चलाने के लिए प्रेरित करते हैं। पश्चिमी राजस्थान में सैंकड़ों किलोमीटर तक बिना मोड़ वाली सड़कें हैं, जहां थकान या झपकी जानलेवा साबित हो रही है। इसके अलावा आवारा मवेशी, गलत ओवरटेकिंग, लेन ड्राइविंग का पालन न करना, सीट बेल्ट नहीं लगाना और नशे में वाहन चलाना दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण हैं।

दौसा जिला इस संकट का जीता-जागता उदाहरण बन गया है। वर्ष 2024 में यहां 713 दुर्घटनाएं हुईं, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 737 पहुंच गई। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि बेहतर सड़कों के बावजूद मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जो बताता है कि समस्या केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं, बल्कि व्यवहार की भी है। सरकार हर साल सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मना कर लोगों को जागरूक करती है। इसके बावजूद सड़क दुर्घटनाएं घटने के बजाय बढ़ती जा रही है। सरकार नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने बढ़ाए हैं, हेलमेट और सीट बेल्ट को अनिवार्य किया है और ऑटोमेटिक चालान प्रणाली लागू की है। बावजूद इसके, नशे में ड्राइविंग के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वर्ष 2024 में राजस्थान में 40 हजार से अधिक चालक शराब के नशे में पकड़े गए, जबकि 2025 में यह संख्या और बढ़ गई। अकेले जयपुर-बांदीकुड़ एक्सप्रेसवे पर वर्ष 2024 में करीब 5 हजार ओवरस्पीड के चालान काटे गए थे, वहीं 2025 में यह संख्या बढ़कर करीब 40 हजार हो गई। यानी ओवरस्पीडिंग पर कार्रवाई में लगभग 9 गुना इजाफा हुआ है। इसके साथ ही राज्य में 900 से अधिक ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए गए हैं, जहां हादसों का खतरा हमेशा बना रहता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि सड़क सुरक्षा को केवल एक अभियान नहीं, बल्कि निरंतर मिशन के रूप में लेना होगा। स्पीड लिमिट का सख्त पालन, ब्लैक स्पॉट्स पर इंजीनियरिंग सुधार, पर्याप्त रोशनी, बेहतर साइन बोर्ड, हाईवे पेट्रोलिंग और दुर्घटना के बाद त्वरित चिकित्सा सहायता से हजारों जानें बचाई जा सकती हैं। साथ ही, जनता को भी यह समझना होगा कि सड़क केवल चलने की जगह नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का साझा मंच है। हाईवे-वैन और एक्सप्रेसवे विकास के प्रतीक हैं, लेकिन यदि रफ्तार पर लगाम नहीं लगी, तो यही सड़कें मौतों की राह बन जाएंगी। जरूरत है संतुलन की-रफ्तार भी हो, लेकिन सुरक्षा के साथ। तभी विकास का यह सफर सच मायनों में सुरक्षित कहा जा सकेगा।

प्रदर्शन



लखनऊ में मंगलवार को स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए नियमों के खिलाफ मंगलवार को लखनऊ यूनिवर्सिटी के पास प्रदर्शन किया।

भारत-इटली संबंध तेजी से अग्रसर हो रहे : इटली के राष्ट्रपति

नई दिल्ली भाषा। इतालवी राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला ने कहा है कि भारत और इटली के संबंध तेज हैं। आगे बढ़ रहे हैं तथा ये पारस्परिक हित के लिए और अधिक बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश "लोकतंत्र एवं कानून के शासन के प्रति समान" जैसे मूलभूत मूल्यों को साझा करते हैं। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू को भेजे अपने शुभकामना संदेश में, मैटारेला ने कहा कि आधुनिक विश्व की द्विपक्षीय एजेंडा के हर क्षेत्र में, साथ ही भारत-यूरोपीय संघ संबंधों के ढांचे के भीतर, "हमारे देशों के बीच तालमेल" मजबूत हो सकता है, जिसे नए आर्थिक और

व्यापारिक समझौते से 'काफी लाभ' होगा।

छब्बीस जनवरी की तारीख वाले शुभकामना संदेश का अंग्रेजी अनुवाद इतालवी दूतावास ने मंगलवार को सप्ताह कीविमर्सेला ने कहा, गणतंत्र दिवस के अवसर पर, मैं आपको, राष्ट्रपति महोदय, भारत गणराज्य के समृद्ध भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। संदेश का यह हिस्सा है कि संयुक्त रणनीतिक कार्ययोजना के कार्यान्वयन की बदौलत द्विपक्षीय साझेदारी, सहयोग के नए अवसरों से 'हर दिन समृद्ध हो रहा है', चाहे वह 'हमारे संबंधित अधिकांश संस्थाओं के बीच संयुक्त'।

परियोजनाओं, वैज्ञानिक सहयोग, या हमारे नगरिक समाजों के बीच तेजी से गहन और फलदायी संपर्कों' के माध्यम से हो।

मेट्रोलास ने यह भी कहा कि दिल्ली और रोम 'लोकतंत्र एवं कानून के शासन के प्रति सम्मान' जैसे मूलभूत मूल्यों को साझा करते हैं। उन्होंने कहा, 'वे कई परस्पर संबद्ध हितों का भी अनुसरण करते हैं। जिन्की शुरुआत नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की सुरक्षा, हिंद-भूमध्य सागर क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता की शांतिपूर्ण प्राप्ति तथा प्रमुख वैश्वक चुनौतियों के प्रभावी बहुपक्षीय प्रबंधन से होती हैं।'

रहेगा। इस साल वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार नौ बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में दूसरी बार सत्ता में आने पर सीताराम को भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनाया था। इसके बाद 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार के 2019 में आने के बाद वित्त मंत्रालय उनके पास ही रहा।

अब तक सीताराम ने फरवरी 2024 के अंतिम बजट सहित कुल आठ लगातार बजट पेश किए हैं। स्वतंत्र भारत में बजट

प्रधान वरखुर्जी ने वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आज बजट पेश किया। मनमोहन सिंह: पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1991 से 1995 के बीच पी वी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए लगातार पांच बजट पेश किए थे। सबसे लंबा बजट भाषण: सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड सीतारामण के नाम है। उनका एक फरवरी, 2020 का बजट भाषण दो घंटे और 40 मिनट तक चला था। उस समय, उन्होंने दो पेज बाकी रहते हुए ही अपना भाषण समाप्त कर दिया था।

पूजा



कोलकाता में मंगलवार को समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ पश्चिम बंगाल में 'कालीघाट मंदिर' में पूजा करते हुए।

विश्व भर में मनाया गया अंतरराष्ट्रीय नरसंहार स्मरण दिवस

वारसों/एपी। बर्लिन में मंगलवार को भोर में नरसंहार स्मरक पर मोमबकियाँ जलाई गईं और यूरोप तथा इससे बाहर लोगों की गतिविधि अंतरराष्ट्रीय नरसंहार स्मरण दिवस मनाते के लिए थम सी गई। यह दिन नाज़ी जर्मनी द्वारा लाखों लोगों की हत्या और महाद्वीप से यहूदियों को पूरी तरह ख़लक करने के लिए किए गए कृत्यों की याद दिलाता है।

अंतरराष्ट्रीय नरसंहार स्मरण दिवस 27 जनवरी को विश्व भर में मनाया जाता है, जो नाज़ी जर्मनी के सबसे कुख्यात मुज्यो शिविरों में से एक 'ऑशविट्ज़-बिर्केनाउ' को सोवियत सेनाओं द्वारा मुक्त कराए जाने का दिन है।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान

जर्मन कब्जे वाले क्षेत्र में शामिल रहे। इनमें
आंशविजय में स्थित समस्त स्थल
पर पूर्व कैरिगों ने 'मृत्यु दीवार' पर
पुष्पाजलि अर्पित की, जहां जर्मन-सैनिक
सेना ने हजारों लोगों की हत्या की
थी, जिनमें से अधिकतर पोलैंड के
नागरिक थे।

जिन में बाद में, पोलैंड के
राष्ट्रपति कैरोल नरोवी की पास के
विशाल स्थल बिरकेनी में उससे
नरादी की देखने वाले समाधि-स्थलों
लोगों के साथ एक स्मरण समारोह
में शामिल होंगे। इस स्थल पर यूरोप
भर से यहूदियों को गैर-जैबों में नाल
डालने के लिए लाया गया था।

नाजी जर्मन सेना ने
आंशविजय में लगभग 11 लाख
लोगों की हत्या की थी, जिनमें से
अधिकतर यहूदी थे, लेकिन

पोलिश, रोमा और अन्य लोग भी शामिल थे।

रेड आर्मी द्वारा 27 जनवरी, 1945 को ऑशविट्ज़ को मुक्त करवा जाने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मंगलवार को पूरे यूरोप में और साथ ही संयुक्त राष्ट्र में भी समारोह आयोजित किए जा रहे हैं।

अपने पड़ोसियों पर युद्ध और नरसंहार थोपने वाला राष्ट्र जर्मनी बुधवार को संसद भवन (बुंडेस्टैग) में एक स्मरण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

इजराइल अप्रैल 1943 में हुए वर्षाओं यहूदी बस्ती विद्रोह की वर्षगांठ पर नरसंहार स्मरण दिवस मनाता है, जो नाजी आतंक के खिलाफ यहूदी प्रतिरोध पर जोर देता है।

सोशल मीडिया ने बदली मिथिला पालकर की जिंदगी

मुंबई/एजेन्सी

‘लिटिल थिंग्स’, ‘कारवां’, ‘चांपस्ट्रिक्स’ और अन्य फिल्मों के लिए मशहूर अभिनेत्री-गायिका मिथिला पालकर आभिर खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म ‘हैप्पी पटेन’ से सुर्खियां बटोर रही हैं। मिथिला फिल्मों से लेकर ओटीटी तक पर अपने अभिनय की कला को दिखा चुकी हैं। अब उन्होंने आईएनएस के साथ अपनी फिल्मिनी जर्नी शेरवती की हैं और बताया है कि उन्होंने कभी भी एक्टर करियर के लिए किसी तरह की प्लानिंग नहीं की, बल्कि सब कुछ अपने आप होता चला गया। अभिनेत्री मिथिला ने कहा, ‘मैंने हमेशा अपने ही कहा है कि अपने पेशेवर जीवन को अगे बढ़ाने के लिए मैंने परिस्थितियों के अनुसार ही काम किया। एक एक्ट्रेस बनने के लिए मैंने इससे दोनों हाथों से अनजाना। मुझे क्या पता था कि इंटरनेट पर बरस देगा? 10 साल पहले, हम सभी इंटरनेट पर बरस शुरूआत कर रहे थे। उस समय टीवी, थिएटर और फिल्मों ही मुख्य थीं। रेडियो का भी अपना एक अलग ही प्रभाव था। इंटरनेट, हमें नहीं पता था कि इंटरनेट से



तर्ह से अपना प्रभाव डाल सकता है। इसलिए, मैं भी सोशल मीडिया पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। मैं हर उस चीज के साथ प्रयोग करने को तैयार थी जो मुझे एक कलाकार बनने में मदद करे।

उन्होंने कहा, मैंने हर चीज के लिए ऑडिशन दिया। मेरी जिंदगी जिस तरह से आगे बढ़ी है,

मुझे नहीं लगता कि मैं इससे बेहतर योजना बना सकती थी। इसलिए मुझे खुशी है कि मैंने इसकी योजना नहीं बनाई, क्योंकि मैंने खुद को इसकी के पत्तो के साथ चलने की आजादी दी। मुझे फिल्टर काँपी मिली, जिससे मुझे 'न्यूज' दर्श हो गया, जो एक नया व्यंग्य कॉमेडी शो था, जिसके बाद धुव और मैंने दो कॉमेडी स्केच किए। उसके बाद, 'लिटिल थिंग्स' हुआ, 'गल्ट इन द सिटी' हुआ। तो, सब कुछ एक के बाद एक होता चला गया। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अगर मैंने इसकी योजना बनाई होती, तो मैं इसे इतनी अच्छी तरह से बना पाती, कारियर की शुल्क और मैं मिथिला को कई लोगों से सहयोग मिलता और वे खुद को लकी मानती है कि उनकी जमीं में उन्हें अछलें लोगों का साथ मिला। अभिनेत्री ने आगे कहा, 'मैं यह जरूर कहना चाहूंगी कि मैं भाग्यशाली थी कि सही समय पर सही लोगों से मिली। जिन लोगों से मैंने 8 साल पहले बात की थी, उसके बाद हमारी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन 8 साल पहले, वे लोग मेरे जीवन में बहुत मायने रखते थे, मेरी यात्रा में उनका बहुत बड़ा योगदान था। और मैं उन लोगों को कभी नहीं भूरींगी।'

जुलूस



प्रयागराज में मंगलवार को आर्मी के जवानों के परिवार के सदस्य प्रयागराज के संगम पर 'गंगा पूजा' जुलूस में हिस्सा लेते हुए

‘मैं हर पल को जी रही हूँ’ : शहनाज गिल

मुंबई/एजेन्सी

पंजाब की 'कटरिना' के नाम से मशहूर अभिनेत्री शहनाज गिल रंगलवार को अपना जन्मदिन मना रही हैं। अभिनेत्री ने अपना जन्मदिन परिवार और करीबी दोस्तों के साथ धूमधाम से सेलिब्रेट किया। इस सेलिब्रेशन का वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। इसमें शहनाज को केक काटते हुए और सबके साथ हंसते-खेलते दिखाया गया। वीडियो के अखिर में शहनाज



सभी के साथ डांस करती दिख रही हैं। साथ ही शहनाज ने भांगड़ा भी किया। वीडियो में सभी के साथ शहनाज बेहद खुश और एनर्जेटिक नजर आ रही हैं। उन्होंने लिखा, आज 27 तारीख अपने हर पल को पूरी त हूं। जन्मदिन मुब मुझे। अभिनेत्री का यह उ को काफी पसंद आ



शहनाज के डांस की जमकर तारीफ कर रहे हैं और जन्मदिन की बधाई भी दे रहे हैं। पंजाब के जालंधर की रहने वाली शहनाज गिल ने करियर की शुरूआत मॉडलिंग से की थी। इसके बाद उन्हें एक म्यूजिक वीडियो में काम मिला। फिर, उन्होंने 'माझे दी जट्टी' और 'पिंड दियां कुडियां' जैसे कई गाने किए, लेकिन लोगों की नजर अभिनेत्री पर गैरी सूध की 'बेबी' से

पडी थी। इसके बाद शहनाज ने पंजाबी फिल्म 'सत श्री अकाव' और 'काला-शा-काला' में काम किया।

अभिनेत्री साल 2019 में 'बिग बॉस 13' में नजर आई थीं। यहां शहनाज ने अपने चुलबुले अंदाज से प्रसिद्धि हासिल की थी। उनकी हाजिरजवाबी, टूटी-फूटी इंग्लिश और सिद्धार्थ शुक्ला से बढ़ती नजदीकियां चर्चा में रहें थीं। बिग बॉस के बाद उन्होंने बॉलीवुड के कई गानों में काम किया।

द 50 : प्रिंस नरूला के बाद अब युविका चौधरी को मिला 'लायन का टिकट'

मुंबई/एजेन्सी

रियलिटी शो 'द 50' जल्द ही दर्शकों के बीच दस्तक देने वाला है। यह शो इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें 50 सेलेब्स नजर आएंगे। कुछ के नामों की घोषणा हो गई है, तो



हर पल चैलेंज करो अब
आखिरकार वो मौका मिल गया।
मैं आ रही हूँ, आप सबको
चैलेंज करने और ये दिखाने के
लिए। युविका चौधरी किसी से
कम नहीं है। अभिनेत्री ने पोस्ट
कर लिखा, एक नई शुरुआत। द
50 के लिए बहुत उत्साहित हूँ।
खबर सुनने के बाद प्रशंसकों के
बीच काफी उमसाह देवने को
मिल रहा है। शो में जिस नरत्ता
बीबी नजर आये, और युविका के
जाने से शो में पावर कपल का
जलवा एक बार फिर देखने को
मिलेगा। दोनों साथ में शो में एंटी
कर रहे हैं। यह शो 1 फरवरी से
जियो हॉटेस्टार और कलर्स टीवी
पर प्रसारित होगा। यह शो
दर्शकों और कंटेस्टेंट को एक
नया और अलग अनुभव देने
वाला है। अब देखना होगा कि
यह शो दर्शकों को कैसा लगेगा।

श्रुति हासन : टैलेंट से बनीं सफल अभिनेत्री और गायिका

नई दिल्ली/एजेन्सी

भारतीय सिनेमा में कुछ नाम ऐसे हैं, जो सिर्फ अभिनय तक सीमित नहीं हैं, जो नाम अपनी बहुआयामी प्रतिभा से एक अलग पहचान बनाते हैं। 1986 वाली वो को अपना जन्मदिन मनाते जानकी श्रुति कमल हासन ऐसी ही हैं। गायिका, संगीतकार और परफार्मेंस, सिनेमिती पहचान केवल एक स्टार किंग के तौर पर नहीं, बल्कि एक मेहनती और टैलेंटेड आर्टिस्ट के रूप में बनी हैं। 1986 में जन्मी श्रुति हासन, भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता कमल हासन और महारथ अभिनेत्री साँकारा दाकुरु की बेटी हैं। हासन परिवार में जन्म लेने के बावजूद श्रुति ने अपनी राह खुद बनाई। वह न सिर्फ एक सफल अभिनेत्री हैं, बल्कि एक स्थापित गायिका और म्यूजिक कंपोजर भी हैं।

जिन्होंने तमिल, तेलुगु और हिन्दी सिनेमा में अपनी मजबूत मौजूदगी कराई है। श्रुति ने चेन्नई के एबार मोटेसरी स्कूल में पढ़ाई की और दस तक वहीं शिक्षा ग्रहण की। इसके मुंबई के सेंट एंड्रयूज कॉलेज स्कूलकोलांगी की पढ़ाई की। बचपन ही उन्हें संगीत और सिनेमा में गहरी रुचि थी। इसी लगाव ने उन्हें अचलकर अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित म्यूजिशियंस इंस्टीट्यूट में पहुँचाया, जहाँ उन्होंने संगीत औपचारिक ट्रैनिंग ली।

महज छह साल की उम्र में श्रुति हासन ने अपने पिता की फिल्म शेरमगन (1992) में पहला गाना गाया जिसे इलेय्या राजा ने कंपोज किया। इसके बाद स्कूल के दिनों में उन्होंने हिंदी फिल्म 'चाची 420' (1997) की गायन किया। साल 2000 में कलकत्ता के निदेशन में बनी फिल्म

राम' में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में अतिथि भूमिका निभाई और उसी फिल्म के लिए हिंदी और तमिल में टाइटल थीम 'रामा रामा' भी गाई। एवम् अभिनेत्री के तौर पर श्रुति ने वयस्क भूमिका में डेब्यू 2009 में बॉलीवुड फिल्म 'लक' से किया। इसके बाद उन्होंने दक्षिण भारतीय सिनेमा की ओर रुख किया और यहीं से उनका करियर नई ऊंचाइयों पर पहुँचा।

श्रुति को असली पहचान तेलुगु फिल्म 'अनानागा ओ धीरुडू' (2011) से मिली। इन फिल्मों में उनके अभिनय ने उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू साउथ दिलाया। इसके बाद उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया। 'रेस गुर्रम' (2014) में दमदार भूमिका के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस तेलुगु मिला। कुल मिलाकर श्रुति के नाम तीन फिल्मफेयर अवार्ड्स सहित

कई सम्मान दर्ज हैं। हिंदी सिनेमा में श्रुति हासन ने 'डी-डे', 'रामैया वरुतायै', 'गब्बर डज बैक', 'वेलम कर्कस', 'रॉकी हंडस' जैसी फिल्मों में काम किया।

जहाँ कुछ फिल्मों को समीक्षकों की सराहना मिली, वहीं कुछ बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं। अभिनय के साथ-साथ संगीत श्रुति हासन की पहचान का अहम हिस्सा है। वह एक स्थापित पार्श्व गायिका है। साल 2009 में उन्होंने अपना पिता के प्रोडक्शन 'उन्नैपुली ओरुवन' से बतौर म्यूजिक जयरेक्टर भी डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने अपना खुद का म्यूजिक भी तैयार किया और बंड है जरिर अपनी पहचान बनाई। श्रुति हासन का सफर इस बात का प्रमाण है कि पहचान नाम से नहीं, काम से बनती है और सुर, रश्मी और भी सेंवेंदाओं का यह संगम भी और भी लंबा चरना है।

सहजपा सिंह रसलूखी जार प्रतीक, सहजपाल, ऋद्धि डोगरा और उर्वशी डोलगिया, चाहत पांडे और नीलम गिरा समेत कल कंस्टेंट के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में अब अभिनेत्री युविका चौधरी का नाम जुड़ गया है। युविका, जो अभिनेता प्रिंस नरसू का पत्नी हैं, उन्होंने खुद शुक्रवार को इंस्टाग्राम के जरिए जानकारी दी कि उन्हें भी लायन का टिकट मिल गया है।

उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें वे कान्नी उषासहित नजर आ रही हैं। वीडियो में युविका कहती हैं, इसी का तो मुझे बेसब्री से इंतजार था। 7 साल हो गए मुझे एक रियलिटी शो किए। मैं इंतजार कर रही थी एक ऐसे बेहतर शो का जो मैंने काबिलियत से मैक करे जो मझे

गणतंत्र दिवस



चेन्नई के अन्नानगर स्थित जयगोपाल गारोदिया विवेकानंद विद्यालय में 77 वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवीनिवृत्त कर्नल ए. श्रीनिवासन रहे, उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और छात्रों का उत्साहवर्धन किया। एन. सोवानथन विशिष्ट अतिथि थे। कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना गीत से हुई, जिसके बाद एनसीसी, आरएसपी, स्काउट्स और गाइड्स द्वारा मार्च पारट प्रस्तुत किया गया।



सनातन धर्म विद्यालय के प्रांगण में 77 वां गणतंत्र दिवस, विद्यालय प्राचार्या एस लता, मुख्य अतिथि विद्यालय की पूर्व छात्रा सी ए संजना आर, विद्यालय कोषाध्यक्ष और खेल समन्वयक सुनील डागा, विद्यालय पाठ्यतर गतिविधि समन्वयक मिरी बागडी, सुश्री श्रवन्ति, अध्यापिकाओं, अभिभावकों और विद्यालय की छात्राओं ने बड़े हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया ध्वजारोहण किया और सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी।



चेन्नई के नम्मलवार स्ट्रीट में स्थित एसएस जैन महिला विद्यालय संघ द्वारा संचालित मांगी केवर अनराज चोरडिया जैन नर्सरी एवं प्राइमरी स्कूल ने अपने प्रांगण में गणतंत्र दिवस मनाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता व रोटरी क्लब ऑफ चेन्नई आईकॉनस के अध्यक्ष नवीन जैन उपस्थित थे। राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया गया।



चेन्नई में मित स्ट्रीट स्थित श्री माहेश्वरी सभा द्वारा माहेश्वरी भवन के प्रांगण में भारत का 77वां गणतंत्र दिवस अत्यंत उत्साह, देशभक्ति और गरिमा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सभा के अध्यक्ष गौरीशंकर राठी के नेतृत्व में कार्यकारिणी, विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे।



चेन्नई में जॉर्ज टाउन स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखा-7 में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस शाखा के मुख्य प्रबन्धक दिनेश कुमार ने झंडारोहण किया। इस अवसर पर शाखा 13 के मुख्य प्रबन्धक मुनुस्वामी, शाखा 3 के प्रबंधक रगोत्तम, चैयरमैन अभिकर्ता सदस्य मुरली रामसेठी, आर नरेन्द्र कांकरिया, कुमार पेरुमाल स्वामी, मुरली सहित अनेक अभिकर्ता उपस्थित थे।



चेन्नई के द्वारका दास गोवर्धन दास वैष्णव कॉलेज (स्वायत्त) में अत्यंत गर्व और देशभक्ति की भावना के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन 5 कंपनी एनसीसी इन्फैंट्री, 1 (तमिलनाडु) बटालियन एनसीसी द्वारा किया गया, जिसमें सचिव डॉ. अशोक कुमार मूंडड़ा, अशोक कुमार केडिया, प्रबंधन समिति, प्राचार्य, महाविद्यालय के शिक्षकगण, कर्मचारी एवं छात्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। यह समारोह देश के समृद्ध लोकतांत्रिक मूल्यों को दर्शाने के साथ-साथ स्वतंत्रता सेनानियों के महान बलिदानों को सम्मानपूर्वक स्मरण करने का अवसर बना, जिन्होंने एक समावेशी और एकजुट भारत के निर्माण में योगदान दिया।



कोयम्बटूर के आरएसपुरम् स्थित राजस्थानी संघ में गणतंत्र दिवस के मौक पर शहीद मेजर संदीप उजीकुण्णन को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए गणतंत्र दिवस मनाया गया। संघ के पदाधिकारियों ने ध्वजारोहण किया।



चेन्नई के ईवीके संपत रोड वेपेरी स्थित अग्रवाल विद्यालय एंड जूनियर कॉलेज में 77 वां गणतंत्र दिवस समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सीसीबी के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त एस.थालर्स सैम राजादुरई ने झंडा फहराया तथा छात्रों के परेड की सलामी ली। विद्यालय की प्रधानाचार्या सी.विजयलक्ष्मी एवं संयुक्त संवाददाता शालिनी अग्रवाल ने पुष्पगुच्छ, शॉल तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर मुख्य अतिथि का सम्मान किया। छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए गए।



चेन्नई। यहां जयगोविंद हरिगोपाल अग्रवाल अग्रसेन कालेज मादावरम में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। मुख्य अतिथि डॉ बी डेनिएल – सेंट्रल ब्राइम ब्रांच वेपेरी चेन्नई के अनुसंधान अधिकारी ने ध्वजारोहण किया। संयुक्त सचिव हरीश कुमार लोहिया, कोषाध्यक्ष बालगोविंद गुप्ता, अध्यक्ष आदित्य अग्रवाल ने अपनी शुभकामनायें प्रेषित की। प्राचार्य डॉ वी गोपी ने सभा का स्वागत किया। उप प्राचार्या डॉ उमा महेश्वरी ने छात्रों को प्रोत्साहित किया।

सुभाषचंद रांका एवं रिखबचंद बोहरा ब्यावर रत्न अवार्ड से सम्मानित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। स्थानीय ब्यावर एसोसिएशन ट्रस्ट द्वारा 77 वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर चेतपेट स्थित लेडी अंडाल कॉन्सर्ट हॉल में एक कार्यक्रम में समाजसेवी सुभाषचंद रांका एवं रिखबचंद बोहरा को उनके समाजोपयोगी कार्यों को रेखांकित करते हुए ‘ब्यावर रत्न अवार्ड’ से सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में ब्यावर एसोसिएशन ट्रस्ट के अंतर्गत मेडिकल रिलीफ फंड सहायता हेतु बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट का भव्य उद्घाटन ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष अजीत गोदी ने इस अवसर पर कहा कि हालांकि यह कार्य ब्यावर एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष के शताब्दी वर्ष पर उनके जन्म दिवस पर शुरू कर दिया गया था परंतु उसका भव्य रूप से शुभारंभ आज किया गया।

ट्रस्ट के मेडिकल चैयरमैन अजय नाहर ने मेडिकल ट्रस्ट की परिकल्पना पर अपने विचार साझा करते हुए बताया कि ट्रस्ट चेन्नई से



लेकर चेंगलपेट तक में बसे अपने स्वजनों के चिकित्सकीय जरूरतों में हर संभव मदद के लिए हाथ बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित है चिकित्सकीय सहायता सुगम और शीघ्र पहुंचे इसके लिए पेमेंट ऑनलाइन मोड में निस्तारित करने का प्रबन्ध किया गया है। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष पक्षीस लाख से अधिक की धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में कमजोर तबके के विद्यार्थियों में बांटी जा रही है और अब ट्रस्ट चिकित्सकीय सहायता हेतु आगे आ रहा है। इस अवसर पर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने दानदाताओं के सिल्वर, गोल्डन

एवं डायमंड वर्गों के दानदाताओं का शॉल एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर ट्रस्ट द्वारा देशभक्ति के जजबे से ओत-प्रोत मनोरंजन कार्यक्रम मेरा भारत महान का आयोजन किया गया जिसमें दिल्ली से पधारे डांस स्मिथ के कलाकारों ने अपनी अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन कर कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रमेश मुथा एवं एम के जैन ने ब्यावर एसोसिएशन ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए इसके उत्तरोत्तर प्रगति की कामना की।

कार्यक्रम के प्रायोजक विशेष रूप से जयपुर से आई शकुंतला गोलेछा, पूर्व अध्यक्ष पुखराज गोलेछा पूलचंद नाहर, प्रेम बोकडियां, शांतिलाल जैन, सी आर जैन, राज कुमार कोठारी सहित ट्रस्ट के सुमित भिड़किया, आकाश जैन, रवि सोगानी, अभय लोढा, महावीर पारख, राकेश लालवानी, महेंद्र कुंकुलोल, ललित रांका, सौरभ संचेरी, अरुण रावोर, कमलेश कोठारी, अमित जैन, प्रशांत, पवनेश, श्रीलोकेश आदि अनेक किए जा रहे सामाजिक कार्यों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए इसके उत्तरोत्तर प्रगति की कामना की।

चेन्नई वॉलीबॉल (डोटा) फेडरेशन के सातवें टूर्नामेंट में वीओजी वॉलीबॉल क्लब बनी विजेता

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। यहां चेन्नई वॉलीबॉल (डोटा) फेडरेशन का सातवां टूर्नामेंट वासुदेव स्पोर्ट्स क्लब के तत्वावधान में वासुदेव जी मंदिर खेल परिसर में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत गायत्री मंत्र से की गई। इस अवसर पर वासुदेव स्पोर्ट्स क्लब के स्तंभ स्व. मेवासिंह पुनिया को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई।

मुख्य अतिथि सुरेंद्र पुनिया एवं राहुल कसवा का माता एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया



गया। फेडरेशन समिति के माणक चौधरी, राजेश सुराणा, अभिनंदन बोथरा, राणाराम पटेल, कानाराम चौधरी एवं तरुण बोथरा ने आयोजक क्लब के सदस्यों को मोमेंटो प्रदान किए। आयोजक अर्जुन देवासी ने बताया कि

टूर्नामेंट में कुल 18 टीमों ने भाग लिया, जिन्हें दो समूहों में विभाजित किया गया। दोनों समूहों से चार-चार टीमों ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल मुकाबलों में वीओजी वॉलीबॉल क्लब एवं माताजी

स्पोर्ट्स ने जीत दर्ज कर फाइनल में स्थान बनाया। फाइनल मुकाबले में वीओजी वॉलीबॉल क्लब ने माताजी स्पोर्ट्स क्लब को पराजित कर चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की। माताजी स्पोर्ट्स उपविजेता रही, जबकि राजेश्वर स्पोर्ट्स क्लब ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।

समापन समारोह में विशिष्ट अतिथि मोहन ने खिलाड़ियों की सराहना करते हुए खेल को बढ़ावा देने पर जोर दिया। विशेष पुरस्कारों में नमन जैन को बेस्ट नेटर, ललित सुराणा को मैन ऑफ द मैच, कानाराम चौधरी को बेस्ट अटेंडर, मादुराम चौधरी को बेस्ट सेंटर तथा राहुल जैन को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया।

रजत द्वारा सेवा कार्य

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। राजस्थानी एसोसिएशन तमिलनाडु (रजत) के सेवा प्रकल्प अनुकंपा के अंतर्गत गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित अनुकंपा का 50वां सेवा कार्यक्रम अत्यंत गरिमान्वय एवं भावनात्मक वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम चेन्नई स्थित श्री महावीर भवन, दादावाडी जैन मंदिर परिसर में आयोजित किया गया। इस विशेष अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नल आर. शिवनाथन (भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी) तथा विशिष्ट अतिथि डॉ. पी. ए. पद्मनाभन, अध्यक्ष-विश्व एवं समूह मुख्य वित्त अधिकारी, राने गुप उपस्थित रहे।



दोनों अतिथियों ने अनुकंपा द्वारा किए जा रहे सतत सेवा कार्यों की सराहना करते हुए इसे मानवता की सच्ची सेवा बताया। कार्यक्रम के दौरान 275 से अधिक बच्चों एवं 50 वरिष्ठ नागरिकों को उपयोगी किट वितरित की गई। इन किटों में बैग, पानी की बोतलें, कंबल, तकिया, नोटबुक, पेन, डेंटल किट, कॉफी मग एवं चॉकलेट

बॉक्स सम्मिलित थे। साथ ही, विभिन्न सेवा संस्थानों को ट्यूबलाइट्स, पेडस्टल फैन, बैटने की बैचें तथा वॉटर डिस्पेंसर जैसी आवश्यक सुविधाएँ भी प्रदान की गईं। आज के इस सेवा प्रकल्प का कुल मूल्य लगभग 10 लाख रहा, जो अनुकंपा की व्यापकता और प्रभाव को दर्शाता है। यह सेवा कार्यक्रम राजस्थानी एसोसिएशन

के अध्यक्ष नरेंद्र श्रीश्रीमाल द्वारा अपनी पूज्य माता स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी की स्मृति में प्रायोजित किया गया। उनके साथ इस पुण्य कार्य में सुभाषचंद रां. रांका एवं एफ. अजीत कुमार चोरडिया ने भी सहयोग प्रदान किया।

कार्यक्रम के अंत में रजत के सचिव दिनेश कोठारी ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।



सूर्य सप्तमी महोत्सव का भव्य आयोजन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। यहां शाकद्विपीय ब्राह्मण समाज द्वारा साहुकारपेट के सूर्य भवन में नंदनम सूर्य नारायण मंदिर में 51वां सूर्य सप्तमी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मीडिया प्रभारी दीपेश देवरा ने बताया कि वसंतपंचमी के दिन भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा

दिवस के छठवें वर्ष पर के उपलक्ष्य में भगवान की पूजा, हवन एवं पंचधातु की मूर्तिका अभिषेक किया गया। मंदिर पर ध्वजा चढ़ाई गई तत्पश्चात आरती, तत्पश्चात अन्न प्रसादन और सूर्य भजन मंडल द्वारा भगवान के निमित्त भजन प्रस्तुत किये गए।

25 जनवरी को सूर्य सप्तमी के अवसर पर नंदनम सूर्य नारायण मंदिर में विद्वान् पंडितों के मंत्र उच्चारण के साथ भगवान सूर्य

नारायण की पूजा, हवन एवं सूर्य देव की मूर्तिका अभिषेक किया गया। शाकद्विपीय समाज के उन सभी मेधावी विद्यार्थियों जिन्होंने पिछले वर्ष- मार्च 2025 में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं और जिन छात्रों ने पिछले वर्ष 2025 की व्यावसायिक पाठ्यक्रम में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया।

सूर्य सप्तमी के सभी लाभार्थियों

का सम्मान किया गया। इस अवसर पर चेन्नई शाकद्विपीय ब्राह्मण समाज के चेयरपर्सन एवं शाकद्विपीय ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष किशोर कुवेरा एवं सह चेयरपर्सन सत्यनारायण भरताणी की गौरवान्वित उपस्थिति रही। चेन्नई शाकद्विपीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष अशोक मथुरा, सचिव चैनराज भरताणी के साथ सभी पदाधिकारी उपस्थित थे।

स्वास्थ्य जांच शिविर



दक्षिण भारत राष्ट्रमत

चेन्नई में गणतंत्र दिवस के मौके पर सिवांची मद्रास जैन संघ द्वारा सिवांची भवन में झंडारोहण समारोह एवं मारुटर हेल्थ बांडी चेक-अप शिविर का सफल आयोजन किया गया। अध्यक्ष चंदनमल श्रीश्रीमाल एवं सचिव नेमीचंद देशरला एवं कार्यकारिणी समिति के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के संयोजक जयतिलाल खिचसरा, राजू सकलेया, गौतम बाफना, संजय बाफना एवं यशवंत चोपड़ा रहे। सिवांची जैन युवा मंडल की युवा टीम का विशेष सहयोग से स्वास्थ्य जांच शिविर में कुल 148 व्यक्तियों ने लाभ प्राप्त किया।